Hkkjrh; turk ikVhZ

(केंद्रीय कार्यालय)
11 अशोक रोड, नई दिल्ली–110001
दूरभाष : 233005700; **फैक्स** : 23005787

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद श्री प्रकाश जावडेकर द्वारा बुधवार, 11 नवम्बर, 2009 को जारी प्रेस वक्तव्य

खाद्य क्षेत्र में मूल्य वृद्धि संप्रग सरकार का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसके तहत सट्टेबाजों को खाद्य पदार्थों के मूल्यों में हेराफेरी करके देश को लूटने की खुली छूट मिल गई है। यह घोटाला खाद्य पदार्थों के वास्तविक अभाव से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि यह जमाखोरी और वस्तु विनिमय के माध्यम से मूल्यों के जैकिंग अप (Jacking up) का मामला है। यह ऐसी स्थिति है, जिसमें किसानों और उपभोक्ताओं का शोषण किया जा रहा है और केवल सट्टेबाज ही फल–फूल रहे हैं। सरकार मूक दर्शक बनी हुई है और इस बारे में कोई गंभीर कार्रवाई करने में किसी तरह की रूचि नहीं दर्शा रही है। सरकार के पास मूल्यों को कम करने के लिए किसी तरह की राजनीतिक इच्छा नहीं है, क्योंकि शासक दल ने इन सट्टेबाजों से भारी मात्रा में चुनावी फंड प्राप्त किया था। ***कांग्रेस को यह नहीं सोचना चाहिए कि हाल की चुनावी सफलता से उसको मूल्य वृद्धि करने का जनादेश प्राप्त हो गया है। भाजपा सरकार को चेतावनी देती है कि यदि सरकार मूल्यों पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने में विफल रहती है तो उसे लोगों का भारी कोपभाजन बनना पड़ेगा।***

यह विडंबना ही है कि जहां सारे विश्व में खाद्य पदार्थों के मूल्यों में कमी हो रही है वहीं भारत में इनमें 70 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी जा रही है। यह भी एक विरोधाभास है कि जबकि चीनी 40 रूपए प्रति कि.ग्रा. और गुड़ 50 रूपए प्रति कि.ग्रा. बिक रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक अपनी खड़ी फसल को इसलिए जला रहे हैं कि उन्हें इसके लाभदायक मूल्य प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इस स्थिति के लिए संप्रग सरकार की नीतियां सीधे तौर पर जिम्मेवार हैं। गत वर्ष कृषि मंत्रालय ने घोषित किया था कि चीनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। सरकार ने तब यह अच्छी तरह जानते हुए चीनी के निर्यात की अनुमति दी थी कि इस वर्ष चीनी की आपूर्ति कम होगी। ***इस निर्णय के परिणामस्वरूप हमने 48 लाख टन चीनी का 12 रूपए प्रति कि.ग्रा. के मूल्य पर निर्यात कर दिया और उसके बाद के 6 महीनों के दौरान ही हमको 70 लाख टन चीनी 27 रूपए प्रति कि.ग्रा. पर आयात करनी पड़ रही है। यह ऐसा घोटाला है, जिसकी जांच सीबीआई से कराए जाने की आवश्यकता है।***

संप्रग सरकार ने खाद्य तेलों में भारत की आत्मनिर्भरता को खत्म कर डाला और उसे पूरी तरह आयात–निर्भर देश बना डाला है। आज हमारा देश अपनी जरूरत का 50 प्रतिशत खाद्य तेल आयात कर रहा है, जो मुख्यतः मलेशिया से किया जा रहा है। संप्रग सरकार देश में खाद्य तेलों की खेती को और खाद्य तेल उद्योगों को नष्ट करने की दोषी है। संप्रग सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ध्वस्त कर दिया और गरीबों के लिए खाद्यान्न की मात्रा को प्रति मास 35 कि.ग्रा. से घटाकर 15–20 कि.ग्रा. कर दिया। संप्रग सकार ने प्राइवेट कंपनियों को किसानों से सीधे खाद्यान्न खरीदने की अनुमति देकर उन्हें मुनाफाखोरी और जमाखोरी करने का खुला अवसर दे दिया।

भाजपा की मांग

- चीनी घोटाले की सीबीआई द्वारा जांच कराई जाए।
- खाद्यान्न वस्तुओं के संग्रह संबंधी नियमों को संशोधित किया जाए।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली को इमदाद देकर उसके माध्यम से दालों, खाद्य तेलों, गेहूँ, चावल और चीनी की आपूर्ति उचित मूल्य पर कराई जाए।
- सरकार दीर्घकालिक कृषि मूल्यन और विपणन मूल्यन नीति की घोषणा करे।
- वस्तु विनिमय के माध्यम से मसालों सहित सभी खाद्य वस्तुओं के वायदा बाजार पर रोक लगाई जाए।

(श्याम जाजू)
मुख्यालय प्रभारी